

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मल वन प्रभाग, सम्मल।
पत्रांक-143/14-1, (कैम्प चन्दौसी) दिनांक, 07/04/2017

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,
विश्व बैंक खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
मुरादाबाद।

विषय- विश्व बैंक पोषित बंदायू-बिल्सी-बिजनौर मार्ग (एस0एच0-51) के चौड़ीकरण हेतु (1) सम्मल में किमी0 58.500 से 107.000 तक 38.80 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6919 वृक्षों के पातन तथा (2) अमरोहा में किमी0 107.000 से 137.500 तक 24.40 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4160 वृक्षों के पातन इस प्रकार दोनों जनपदों के समेकित प्रस्ताव में कुल 63.2 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11079 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं0-8वी/यू0पी0/06/10/2016/एफ0सी0/545 दि0 09-03-2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दि 09-03-2017 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्त सं0-1 से 6 तक निम्न प्रकार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (63.20X 2= 126.40 हे0) अर्थात् 126.40 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (सम्मल वन प्रभाग की दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 126.40 हे0 भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुक्षण की धनराशि रु0- 1,53,63,000/-) (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा द्वारा अपने प्रभाग के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि की मांग याचक विभाग से कर वांछित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

2 (क) प्रयोक्ता अनीकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि (सम्मल वन प्रभाग की एन0पी0वी0 की धनराशि रु0- 24288800/-) ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा, वन प्रभाग, अमरोहा द्वारा अपने प्रभाग के अन्तर्गत शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की आवश्यक धनराशि की मांग याचक विभाग से कर वांछित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

2 (ख) इसके उपरान्त याचक विभाग द्वारा ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृती की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृती पर विचार किया जायेगा।

2 (ग) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विधिवत् स्वीकृती जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा। और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

4- प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) सेन्ट्रल जोन बैंक, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं0-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16-11-2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सडक के दोनों तरफ तथा मिडेन पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

5- प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।

6- राज्य सरकार प्रकरण में किसी भी प्रकार का शासनादेश जारी करने से पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता के नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करेंगी।

उक्त प्रकरण में चौड़ीकरण कार्य के अन्तर्गत जनपद सम्मल में बाधक वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृती भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्गत की जा चुकी है। उक्त प्रस्ताव में सम्मलित बाधक वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है।

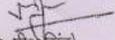
क्रम सं0	जनपद	वृक्षों की सं0 (गर्त > 30 से0मी0)
1	सम्मल	6919

छपान:- बाघक वृक्षों के छपान हेतु धनराशि (प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-प-105/16-57 (लाट) दि० 23-9-2014 के बिन्दु सं०-2 में हुए संशोधन के अनुसार रू० 10/- प्रति वृक्ष के आधार पर) 6919 वृक्ष दर 10/- रू० प्रति वृक्ष) रू० 69190/- का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मल वन प्रभाग, सम्मल के नाम देय हो प्रस्तुत करें। यह भी अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा, वन प्रभाग, अमरोहा द्वारा अपने प्रभाग के अन्तर्गत बाघक वृक्षों के छपान हेतु आवश्यक धनराशि की मांग याचक विभाग से कर वाञ्छित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या पत्रांक-II/FC/ROC/95-2011/part-v/1227 02-02-2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृती जारी की जायेगी। याचक विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी। जब तक वन भूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते हैं।

कृपया उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन अतिशीघ्र करने का कष्ट करें ताकि शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। परिपालन आख्या के उपरान्त ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृती जारी की जायेगी।

भवदीय,


(एम० पी० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्मल वन प्रभाग, सम्मल।

पत्रांक 1431 / उक्तदिनांकित।

- 1- प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को विषयक क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- प्रतिलिपि:- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- क्षेत्रीय वनाधिकारी, चन्दौसी/गुनौर को सूचनार्थ प्रेषित।

(एम० पी० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्मल वन प्रभाग, सम्मल।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा।

पत्रांक 3141 / 14-1, दिनांक, अमरोहा, अप्रैल, 19 2017,
सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता

विश्व बैंक खण्ड,

लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद।

विषय :- विश्व बैंक पोषित बदायू-बिल्सी-बिजनौर मार्ग (एस.एच-51) के चौड़ीकरण हेतु (1) सम्भल में किमी⁰ 58.500 से 107.00 तक 38.80 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6919 वृक्षों के पातन तथा (2) अमरोहा में किमी⁰ 107.00 से 137.500 तक 24.40 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4160 वृक्षों के पातन इस प्रकार दोनों प्रभागों के समेकित प्रस्ताव के कुल 63.2 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11079 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं०-8बी/यू०पी०/०६/१०/२०१६/एफ०सी०/५४५ दिनांक ०९.३.२०१७, तथा इस कार्यालय का पत्र संख्या २०१४/२२-१, दिनांक ३०.०३.२०१७.

महोदय

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक ०९.०३.२०१७ द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्त सं०-१ से ५ तक निम्न प्रकार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

१. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् (24.4x2=48.800) अर्थात् 49.00 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (अमरोहा वन प्रभाग की दुगुने अवनत वनभूमि अर्थात् 49.00 हे० भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं १० वर्षों के अनुरक्षण की धनराशि ₹ 83,30,000/-) (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

२. (क) माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये, आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की धनराशि (अमरोहा वन प्रभाग की एन०पी०वी० की धनराशि ₹ 15274400) ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(ख) इसके उपरान्त याचक विभाग द्वारा ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये। तदुपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वन बढ़ता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन०पी०वी० की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

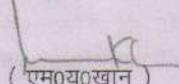
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विधिवत् जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा। और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बढ़ता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) सेन्ट्रल जोन बैंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं0-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा मिडेन पर (यदि उपलब्ध हो तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।

उक्त प्रकरण में चौड़ीकरण कार्य के अन्तर्गत जनपद अमरोहा में बाधक वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्गत की जा चुकी है। उक्त प्रस्ताव में सम्मिलित बाधक वृक्ष 4160 का छपान किये जाने हेतु 10/रु0 प्रति वृक्ष की दर से रु0 41600/- का बैंक ड्राफ्ट जोकि प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा के नाम से देय हो प्रस्तुत करें।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या पत्र- II/Fc/Roc/95-2011/Part-v/1227 दिनांक 02 फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी, जब तक वन भूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते हैं। कृपया उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन अतिशीघ्र करने का कष्ट करें, ताकि शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। परिपालन आख्या के उपरान्त ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

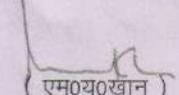
भवदीय


(एम0यू0खान)
प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा।

पत्रांक 3141 / दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।
3. क्षेत्रीय वनाधिकारी हसनपुर।


(एम0यू0खान)
प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा।